

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 680]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2017—अग्रहायण 29, शक 1939

वित्त विभाग  
(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2017

क्र. 374-25-2017-आनीविइ-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (1) तथा अनुच्छेद 243-म के खण्ड (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 66-25-2017-आनीविइ-चार, दिनांक 20 मार्च 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“5. आयोग अधिसूचना दिनांक 20-3-2017 के पैरा 4 में संदर्भित विषय पर 31 जनवरी, 2018 तक उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. अनुशंसा 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 पांच वर्ष की कालावधि के लिए होगी, जो पन्द्रहवें वित्त आयोग की कालावधि के समवर्ती है.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज गोविल, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2017

क्रमांक 375-25-2017-आनीविइ-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज गोविल, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 20th December 2017

No. 374-25-2017-EPAU-IV.—In pursuance of the provisions of clause (1) of Article 243-I and clause (1) of Article 243-Y of the constitution of India, read with Section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the Governor of Madhya Pradesh hereby makes following amendment in this department's Notification No. 66-25-2017-EPAU-IV, dated 20<sup>th</sup> March, 2017, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, for Para 5, the following Para shall be substituted, namely:—

“5. The Commission shall submit its report by January 31, 2018 on the subject referred to in Para 4 of the Notification dated 20-3-2017, The recommendation shall cover the period of five years from 01<sup>st</sup> April, 2020 to 31<sup>st</sup> March, 2025 which is concurrent with the period of the Fifteenth Finance Commission.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
MANOJ GOVIL, Principal Secy.